ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

रविवारीय 25-31 अगस्त 2019, संस्करण-1, अंक -3 | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN 00962 | कुल प्रष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

पेजः 4
झारखंड कैसे बना मत्स्य उत्पादन में चैंपियन

अलविदा अरूण जेटली

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली का 24 अगस्त को निधन हो गया। अरूण जेटली लंबे समय से बीमार थे उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। 2019 में लोक सभा चुनावों में भाजपा की जीत के बाद भी उन्होंने अस्वस्थता की वजह से मंत्री बनने से मना कर दिया था।

1952 में जन्में अरूण जेटली ने भाजपा सरकार में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले। 1974 में दिल्ली से छात्र राजनीति में कदम रखने वाले अरूण जेटली ` जेपी आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे और 19 महिने तक जेल में भी रहे। जेटली ने श्रीराम कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया उसके बाद लॉ की पढाई की । वह देश के दिग्गज वकीलों में गिने जाते थे। कई मौकों पर उन्होंने भाजपा के लिये संकटमोचक का काम किया। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से ऊपर सबों से मित्रता रखने वाले क्रिकेटप्रेमी मृदुभाषी और संसद में तथ्यों के साथ बहस करने वाले अरूण जेटली को नोटबंदी, जनधन, जीएसटी जैसे कामों के लिये जाना जायेगा। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री है। वह दिल्ली वासी थे और दिल्ली से उन्हें बहुत लगाव था।

◇सालों पहले हरमू में बना विद्युत शवदाहगृह नहीं हो सका चालू ◇भवन परिसर कभी आश्रम था अब इसमें चलते हैं खटाल

मुक्तिधाम को नहीं मिल सकी मुक्ति

●लोगों के अनुसार डमरू बाबा आश्रम को ध्वस्त कर बना था विद्युत शवदाह गृह

●चालू हो जाने से लकड़ियों की बर्बादी, प्रदूषण और परेशानी से मिलती मुक्ति

रांची : सालों पहले काफी जद्दोजहद के बाद हरमु में बना विद्युत शवदाह गृह बिना चालु हुये ही जर्जर होकर बेकार हो गया है। इसके बनने के समय भी बहुत विवाद हुआ था।

वर्तमान में शवदाहगृह का जो भवन है पहले वह मुख्य हरमु पूल के बाद बायीं और इलेक्ट्रिक फीडर से सटे सरना मसना स्थल में बन रहा था, लेकिन सरना धर्मावलंबियों के भारी विरोध के बाद काम रोक दिया गया था और उस-के बाद फोर्स लगा कर यह निर्माण शरू करवाया गया उसके कुछ अवशेष आज भी सरना मसना स्थल पर दिख जायेंगे । क्रुद्ध सरना धर्मावलंबियों ने यहां भीड़ जुटा कर पुलिस पर हमला कर दिया और बन रहे भवन को ढहाना शुरू कर दिया। पहले पुलिस भाग खड़ी हुयी और बाद में अतिरिक्त फोर्स मंगा कर प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाये गये। अंत में भारी विरोध को देखते हुये विद्युत शवदाह गृह का निर्माण वहां टाल दिया गया और वर्तमान में स्थित भवन को बनाया गया। जो आज तक चालु ही नहीं हो पाया। बीच बीच में इससे संबंधित इक्का दुक्का खबरें चर्चा में आयीं, पर किसी ने भी इसके लिये ठोस पहल नहीं की। अगर विद्युत शवदाहगृह चालु हो गया होता तो हर माह टनों लकड़ी इंतजाम करने और उसके दहन से पर्यावरण के नुकसान एवं घंटो के परेशानी सभी से मुक्ति मिलती।

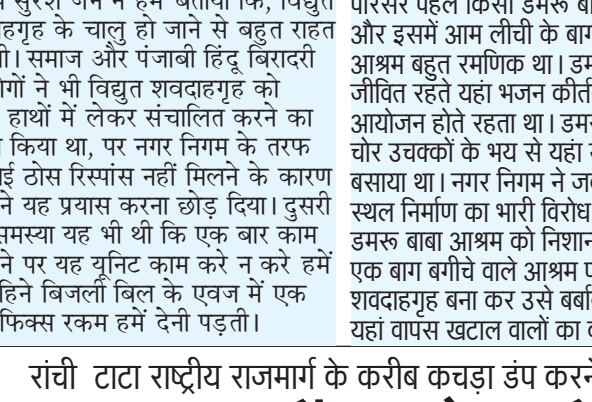

भवन में हैं खटाल वालों का सामान

परिसर में अब खटाल चलता है

क्यों नहीं चालु हो सका विद्युत शवदाह गृह?

नगर निगम ने कई बार इसे संचालित करने के लिये टेंडर निकाले, पर कोई भी इस काम के लिये आगे नहीं आया। निर्माण के बाद एक बार टेस्टिंग की गयी, पर यहां आस पास के लोगों का कहना है कि वह भी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाया था। फर्नेस के लिये यहां अलग से ट्रांसफर्मर लगाये गये हैं जो अब जर्जर होकर मुंह चिढा रहा है।

हर महिने चार पांच बड़े ट्रक लकड़ी की होती है खपत

मारवाड़ी समाज टिंबर व्यवसायियों से मुक्तिधाम के लिये हर महिने बड़े ट्रक से चार-पांच ट्रक लकड़ी खरीदता है। बरसात में लकड़ी की कमी को देखते हुये स्टॉक कर के भी रखा जाता है। टिंबर वाले भी उपलब्धता के अनुसार तीन रूपये से लेकर पांच रूपये प्रति किलो तक कीमत लेते हैं। सुरेश जैन ने बताया कि, टिंबर वालों को यह जानकारी रहती है कि कैसी लकड़ी यहां देनी है।

पंजाबी हिंदू बिरादरी एवं मारवाड़ी समाज ने भी किये थे प्रयास

वर्तमान में हरमु मुक्तिधाम का संचालन मारवाड़ी समाज करता है। समाज के एक सदस्य सुरेश जैन ने हमें बताया कि, विद्युत शवदाहगृह के चालु हो जाने से बहुत राहत मिलती। समाज और पंजाबी हिंदू बिरादरी के लोगों ने भी विद्युत शवदाहगृह को अपने हाथों में लेकर संचालित करने का प्रयास किया था, पर नगर निगम के तरफ से कोई ठोस रिस्पांस नहीं मिलने के कारण सबों ने यह प्रयास करना छोड़ दिया। दुसरी एक समस्या यह भी थी कि एक बार काम ले लेने पर यह यूनिट काम करे न करे हमें हर महिने बिजली बिल के एवज में एक मोटी फिक्स रकम हमें देनी पड़ती।

डमरूबाबा आश्रम को ध्वस्त कर बना था शवदाहगृह

हमने जब सहां के स्थानीय लोगों से बातचीत की तो पता चला कि वर्तमान शवदाहगृह का परिसर पहले किसी डमरू बाबा का आश्रम था और इसमें आम लीची के बाग बगीचे थे। आश्रम बहुत रमणिक था। डमरू बाबा के जीवित रहते यहां भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन होते रहता था। डमरू बाबा ने ही चोर उचक्कों के भय से यहां खटाल वालों को बसाया था। नगर निगम ने जब सरना मसना स्थल निर्माण का भारी विरोध देखा तो उसने डमरू बाबा आश्रम को निशाना बनाया और एक बाग बगीचे वाले आश्रम परिसर में विद्युत शवदाहगृह बना कर उसे बर्बाद कर दिया। अब यहां वापस खटाल वालों का कब्जा है।

अदृश्य शक्तियां यहां शव जलने ही नहीं देंगी?

मुक्तिधाम के पास ही रहने वाले हवलदार यादव का अपना ही तर्क है।वे कहते हैं यह डमरू बाबा का आश्रम था नगर निगम ने सरकारी नौकरी का लालच देकर शवदाहगृह बनाने के लिये राजी कर लिया। यह गलत हुआ। आश्रम में तीन विशाल कुयें थे उसके चबूतरे पर सैकड़ो लोग उठते बैठते थे सब को नगर निगम ने ध्वस्त कर दिया। यहां आज भी इतनी शक्ति है कि, यह चालू नहीं हो सकता। और जो भी इसकी कोशिश करेगा उसका नुकसान होगा। जिस ठेकेदार ने इसे बनवाया उसका भयंकर दुर्घटना हो गया दोनो पैर टूट गये ।

एसोचैम के आयोजित सेमिनार में नवीन जायसवाल, जीतूचरण राम एवं सीपी सिंह हुये शामिल नगर विकास मंत्री ने कहा

मिलावट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध करायें

आलोक कुमार मिश्रा

रांचीः एसोचैम द्वारा एक सेमिनार का आयोजन शुक्रवार को राजधानी रांची में किया गया । इस सेमिनार के जरिए झारखंड फूड एग्रीकल्चर और डेयरी इन्वेस्टमेंट में कहां है, किस स्थान पर खड़ा है इस बिषय पर चर्चा की गई साथ ही इस क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस प्रकार हो इसको लेकर भी मंथन किया गया। कृषि विभाग के विशेष सचिव सह सलाहकार प्रदीप कुमार हजारी ने कहा कि भारत सरकार ने अभी हाल में ही एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लागू की है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सहयोग से एक प्रयास किया गया जिसके नतीजे में गुमला, सरायकेला, जमशेदपुर की किसानों द्वारा भिंडी की ऐसी पैकिंग की गई जो दुबई के मार्केट में सप्लाई किया गया। आने वाले समय में झारखंड देश का ऐसा राज्य बन सकता है जहां से हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहां से अभी कई चीज़े एक्सपोर्ट की जा रही है। इस सेमिनार में राज्य के बाहर से आए लोगो ने भी अपनी बातें सामने रखी।

कार्यक्रम में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जसवाल, कांके विधायक जीतूचरण राम, सहित कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही।

नगर विकास मंत्री सी पी सिंह ने कहा की आज लगभग सारी चीजों में मिलावट हो रहे हैं जिस कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं। जो भी कंपनी खादय पदार्थ का निर्माण करती है वो लोगो तक गुणवत्ता वाली सामान उपलब्ध कराये ताकि लोगो के स्वास्थ्य सही रह। आजकल लोग सस्ती चीजों की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले सामान थोड़े महंगे जरूर होते हैं पर हानिका-रक नहीं होते हैं।उन्होंने सरकार की ओर से लाए जा रहे योजनाओं पर भी चर्चा की उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर

- झारखंड पूरे देश भर में 19 में रैंक पर है झारखंड जीडीपी में 1.53 योगदान देता है।
- इस नेशनल सम्मिट में इस बात पर भी चर्चा की गई कि आखिर इन्वेस्टर झा रखंड में क्यों इन्वेस्ट करें?
- कृषि के क्षेत्र में 83% प्राइवेट इन्वेस्टर आ चुके आज झारखंड से लगभग 4 से 5 करोड़ की सब्जी दिल्ली जैसे शहरों में हम भेज रहे हैं

किसानों के लिए कार्य कर रही है ताकि उनकी आय दुगनी हो जाए

इस फूड एग्रीकल्चर और डेयरी नेशनल समिट में कृषि के क्षेत्र में हो रहे बदलाव पर भी चर्चा की गई जिसमें बताया गया की इंडियन एग्रीकल्चर में इस बार के बजट में 151000 करोड़ रुपए पास किए गए जबकि पिछले बजट को देखा जाए तो 86000 करोड रुपए था अगर हम बात करें झारखंड की तो इस बार झारखंड में कुल 7225 करोड रुपए का कृषि बजट पास किया गया। डॉक्टर झा का कहना था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और पैसे भी हैं जिसका प्रयोग कर हम काफी आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को भी सुधार सकते हैं।

इस समिट में मौजूद अलग-अलग क्षेत्र से आए लोगों ने भी अपने विचार साझा किए जिसमें कुछ लोगों की मांग थी की फूड एग्रीकल्चर और डेयरी के क्षेत्र में भी पढ़ाई सभी यूनिवर्सिटी ओं में होनी चाि-हए। इस बात पर भी जोर दिया गया कि प्रा-इवेट इन्वेस्टर्स को झारखंड में कैसे लाया जाए झारखंड का कैसे प्रमोशन किया जाए फूड एंड एग्रीकल्चर क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिले।

रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब कचड़ा डंप करने और मरे हुये जानवरों को फेंकने से फैल रहा है दुर्गंध

नामकुम हाइटेंशन मैदान के पास सड़क पर ही कचड़ा डंप

सिदाम महतो

रांचीः राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर कई यात्री गुजरते हैं। अपने राज्य की तथा देश के अलग अलग हिस्से से भी कई गाड़ियां यहां से गुजरती है। लेकिन यहां से होकर गुजरने वाले मन में झारखंड की एक गंदी तस्वीर लेकर ही जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 33 ,उद्योग नगरी जमशेदपुर और झारखण्ड की राजधानी रांची को जोड़ता है। इसी राजमार्ग पर नामकुम ओवरब्रिज रांची का मुख्य द्वार बन जाता है। जहां से होकर सुवर्णरेखा नदी बहती है इसी ओवरब्रिज के हाइटेंशन मैदान छोर पर ,सड़क किनारे ही कचरा डम्प किया जा रहा है। मरे हुए जानवर को फेंका जा रहा है।जिससे यहाँ दुर्गन्ध फ़ैल रहा है। दुर्गन्ध से बचने के लिए कुछ देर नाक को बन्द करना पड़ता है। नाक को रुमाल से ढकना पड़ रहा है।लगभग 100 मीटर की दुरी पर स्व दुर्गा सोरेन चौक है, वहां कई महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित है। पास ही हाइटेंशन

मैदान है। जहां बच्चे फुटबॉल -क्रिकेट खेलते हैं। लोग इधर सुबह-शाम टहलने के लिए भी आते हैं।किसी भी शहर में आने वाले मेहमान शहर की मीठी यादें लेकर जाते हैं। साफ -सफाई की व्यवस्था को याद करते हैं।पर यहां स्वागत और विदाई दुर्गन्ध से हो रही है।

ज्ञात हो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में झारखंड को बेस्ट परफार्मिंग स्टेट में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति रामनाथ गोविन्द के हाथों झारखण्ड के नगर विकास मंत्री अवार्ड ग्रहण कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त रांची बेस्ट 50 शहरों में साफ सफाई के मामले में 46 वें नम्बर पर आता है।

कैपिटल सिटी में बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए सम्मान भी रांची को प्राप्त है। पर राजधानी रांची के मुख्य द्वार पर फ़ैल रही तीव्र दुर्गन्ध और गंदगी से इस सम्मान को ठेस पहुंच रहा है।

बालाजी डेंटल केयर

समस्त दंत रोगों की चिकित्सा उपलब्ध।

Address: Shiv Bhawan, Laah Kothi, Ratu Road, Ranchi-5
Ph. 9006833759

भारत के युवाओं को मिला संयुक्तराष्ट्र के पहले यूएन यूथ क्लाइमेट सम्मिट के लिये ग्रीन टिकट

संयुक्त राष्ट्र ने 20 अगस्त को घोषणा की कि दुनिया भर से चुने गए 100 उत्कृष्ट युवा जलवायु चैंपियन को शनिवार 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यूएन यूथ क्लाइमेट समिट में भाग लेंगे।

"ग्रीन टिकट" विजेता संयुक्त राष्ट्र में पहली बार यूथ क्लाइमेट समिट में भाग लेने के लिए चुने गए 500 से अधिक युवा जलवायु नेताओं में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन युवा जलवायु नेताओं को एक वैश्विक मंच पर अपने समाधान प्रदर्शित करने और हमारे समय के निर्णायक मुद्दे पर निर्णय लेने वालों के साथ सीधे जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। युवा नेता सोमवार 23 सितंबर को जलवायु एक्शन शिखर सम्मेलन में युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की चर्चाएँ प्रस्तुत करेंगे। 100 'ग्रीन टिकट' विजेता युवा जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क के लिए कार्बन-तटस्थ के रूप में वित्त पोषित यात्रा प्राप्त करेंगे, 18 से 29 वर्ष की आयु के बीच 7,000 से अधिक आवेदकों के समूह से चुने जाने के बाद, उनकी प्रदर्शन प्रतिबद्धता के आधार पर जलवायु संकट को दूर करने और समाधान को आगे बढ़ाने के लिए। प्राप्तकर्ता सभी क्षेत्रों के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

100 'ग्रीन टिकट' पाने वालों में भारत के एक युवा जलवायु कार्यकर्ता पीआर विष्णु हैं, जो उ-5 फाउंडेशन (चेंज चेंज क्लाइमेट चेंज) के संस्थापक सीईओ हैं और जलवायु परिवर्तन, झुग्गी पुनर्वास, आदिवासी विकास जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और आपदा जोखिम में कमी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक वीडियो संदेश में ग्रीन टिकट प्राप्तकर्ताओं और

सभी सफल आवेदकों को बधाई देते हुए कहा, "मैं दुनिया भर के युवाओं से अपील करता हूं कि वे ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का पालन करें और अपने देशों में जलवायु कार्रवाई के चालक बनें।"युवा लोग जो व्यक्तिगत रूप से भाग लेने में असमर्थ हैं, उन्हें ट्विटर या इंस्टाग्राम पर "यूथ # क्लेमेटएक्शन समिट" वाक्यांश के साथ एक सेल्फी वीडियो साझा करके मेरा भविष्य हमारा ग्रह अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह घोषणा करते हुए कि वे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पहले से ही क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और अपने नेताओं को अब जलवायु कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। वे स्थानीय संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यायों में भी शामिल हो सकते हैं; पर्यावरण पर कम हानिकारक प्रभावों के लिए विकल्प बनाना जारी रखें और संयुक्त राष्ट्र के एक्टनॉ अभियान के माध्यम से इन प्रयासों को ट्रैक करें; और यूएन वेब टीवी पर लाइवस्ट्रीम के माध्यम से युवा जलवायु शिखर सम्मेलन में धुन। संयुक्त राष्ट्र युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की वेबसाइट पर आने वाले हफ्तों में संलग्न करने के अधिक तरीकों की घोषणा की जाएगी।

यूथ क्लाइमेट समिट में प्रोग्रामिंग का पूरा दिन होगा, जो युवा कार्यकर्ताओं, नवोन्मेषकों, उद्यमियों, और परिवर्तन निर्माताओं को एक साथ लाता है जो विज्ञान द्वारा प्रदर्शित गति और पैमाने पर जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह जीवन के सभी क्षेत्रों से युवा नेताओं के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के साथ, एक्शन-ओरिएंटेड, इंटरजेनेरेशनल और समावेशी होगा

यूथ क्लाइमेट समिट महासचिव क्लाइमेट एक्शन समिट से पहले एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो सरकार, व्यापार और नागरिक समाज के नेताओं से जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए बुला रहा है और 20 सितंबर को ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक के एक दिन बाद आता है।

"युवा लोग जलवायु कार्रवाई के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं," महासचिव के दूत ने युवा, जयम्मा विक्रमनायके पर कहा। सकारात्मक जलवायु समाधान चलाने के लिए एक शक्तिशाली वैश्विक मंच प्रदान करेगा"।

अमेजन का दावानल

दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी अमेजन। अमेजन की द्रोणी में है विश्व के सबसे घने और विशालकाय वर्षा वन जिन्हें अमेजन का जंगल कहते हैं। इस जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में आता है। इस अमेजन जंगल में आग लग गयी और जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जल कर खाक हो गया। इसे बुझाने के सारे प्रयास विफल होते गये और जंगल इस भयंकर दावानल की चपेट में बर्बाद होता गया। अब इसकी भरपाई बहुत ही मुश्किल है। एक वन को सघन होने में सालों लगते हैं, पर आग, पेड़ों की कटाई का काम कुछ ही घंटों में इन वनों का विनाश कर देते हैं। ब्राजीज के प्रमुख महानगर साओ पाउलो के आसमान पर अमेजन जंगलों की आग के धुंये छा गये हैं और दिन में भी अंधेरा हो गया है। आग का फैलाव इतना तेज है कि अब यह वोलिविया और पराग्वे के जंगलों तक पहुंच गयी है। अस बीच यूरोपीय देशों ने ब्राजील पर आग बुझाने में लापरवाह होने का आरोप भी लगाया है। ब्राजील में लोग सड़कों पर आग बुझाने के लिये प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आग पर काबू के लिये सेना को लगाया गया है।

हमारी पृथ्वी के लिये इससे बुरा और क्या हो सकता है? कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील के अमेजन वर्षावनों में भयंकर आग लग गयी और प्रति मिनट एक फुटबॉल के आकार के जंगल इसकी चपेट में आते गये। अमेजन के इन जंगलों को दुनिया का फेफड़ा कहते हैं और पृथ्वी पर बीस प्रतिशत ऑक्सीजन इन्हीं अमेजन जंगलों से प्राप्त होता है।

कल्पना किजिये जैव विविधताओं वाले इन अमेजन जंगलों में आग की विनाश लीला में पेड़ों के अलावा कितने ही जीव जंतु तड़प कर मर गये होंगे? वहां से प्राप्त तस्वीरों में बंदरों की एक बहुत ही सुस्त प्रजाति जो तेज दौड़ भी नहीं सकती उसे कुछ वनकर्मी उठाये हुये बाहर निकाल रहे हैं। हॉलीवूड की बहुत सारी फिल्मों की पृष्ठभूमि अमेजन के जंगल रहे हैं। चर्चित अनाकोंडा फिल्म की शूटिंग यहीं हुयी, और यहां के जीव जंतुओं पर असंख्य रोचक फिल्में एवं वृतचित्र बनाये गये हैं।

इन सब से भी दुःखद बात ये है कि ब्राजील के राष्ट्रपति ने आशंका जतायी है कि बहुत सारे संगठनों को ब्राजील की सरकार ने वन बचाने के नाम पर चंदा नही दिया और इन संगठनों और संस्थाओं ने जान बूझ कर ये आग लगायी है। अगर इन आरोपों में थोड़ी भी सच्चाई है, तो हम मनुष्यों के लिये इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इस बीच एक छोटी सी राहत की खबर ये है कि वहां बारिश हुयी है जिससे आग पर कुछ हद तक अंकुश लगा है। जंगलों में लगी आग को बुझाना बहुत ही दुष्कर काम होता है। हेलीकॉप्टर से पानी लेकर उड़ान भरना और आग पर छिड़काव कर उसे बुझाया जाता है, जो किसी छोटे एरिया में तो कारगर होता है, पर अमेजन के विशालकाय जंगलों में यह ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। यह एक वास्तविकता है कि इस आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल है।

अमेजन का मतलब महिला योद्धा होता है, जो कभी हारती नहीं। लेकिन अमेजन जंगलों के इस आग और बर्बादी ने इस बार इस योद्धा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जिसकी भरपाई अब सालों तक नहीं हो पायेगी।

अमेजन के आग की सैटेलाइट फोटो

बाढ के साथ जीने की कला विकसित करनी चाहिये

भरत झुनझुनवाला

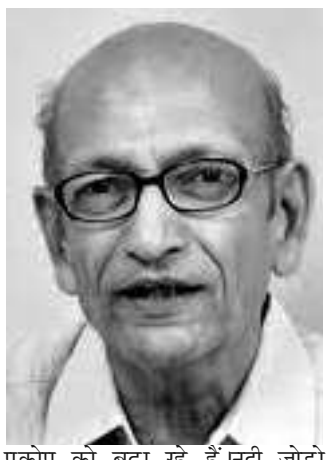

वर्तमान में देश में एक स्थान पर सूखा तो दूसरे स्थान पर बाढ़ आ रही है। यह विचार पनपता है कि बाढ़ के क्षेत्र से यदि पानी को सूखे क्षेत्र तक पहुंचा दिया जाये तो दोनों ही क्षेत्रों की समस्या हल हो जाएगी। यह धारणा इस सोच पर आधारित है कि कुछ नदियों में जरूरत से अधिक पानी उपलब्ध है। इतना सही है कि कुछ नदियों में बाढ़ आती है और उससे जानमाल का नुकसान होता है। लेकिन इसके सामने बाढ़ के कई लाभ भी हैं। सबसे बड़ा लाभ है कि बाढ़ का पानी विस्तृत क्षेत्र में फैलता है, जिसके कारण पानी भूगर्भीय तालाबों में रिस्ता है। लगभग 1 मीटर पानी का स्तर उसे 1 किलोमीटर दूर तक पहुंचा देता है। यानी बाढ़ का पानी 100 किलोमीटर दूर आपको 100 मीटर की गहराई पर मिल जायेगा। अतः बाढ़ से लगभग 200 किलोमीटर क्षेत्र में भूगर्भीय जल का पुनर्भरण होता है। इस प्रकार बाढ़ के पानी को यदि हम दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं तो देने वाले क्षेत्र में पुनर्भरण कम होगा। तदनुसार सिंचाई कम होगी जबकि पानी प्राप्त करने वाले क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार होगा।

बाढ़ का दूसरा लाभ है कि कई वर्षों से नदी के पेटे में जमा हो रही गाद को बाढ़ बहा कर समुद्र तक ले जाती है। यदि बाढ़ नहीं आये तो पानी में वेग उत्पन्न नहीं होता है जो कि जमी हुई गाद को सागर तक पहुंचा सके। यदि गाद समुद्र तक न पहुंचाई जाये तो नदी का तल ऊंचा हो जाता है और बाढ़ ज्यादा आती है। बड़ी बाढ़ को रोक कर हम वास्तव में हर साल आने वाली बाढ़ के प्रकोप को बढ़ा रहे हैं।नदी जोड़ो परियोजना में एक और समस्या है। कोई भी राज्य अपना पानी देने को तैयार नहीं है। जैसा कि हम पंजाब एवं हरियाणा तथा कर्नाटक एवं तमिलनाडु के विवादों में देख रहे हैं। पंजाब में कुछ क्षेत्रों में जलभराव हो रहा है। फिर भी पंजाब अपना पानी देने को तैयार नहीं है। इस परिस्थिति में अन्तर्राज्यीय नदी जोड़ने के कार्यक्रम कतई सफल नहीं हो सकते हैं। अधिकाधिक एक ही राज्य में बहने वाली दो नदियों को जोड़ने का छोटा-मोटा प्रयास किया जा सकता है।

लेकिन यह भी सही है कि यदि पंजाब में जलभराव हो रहा है और राजस्थान में सूखा आ रहा है तो देश के लिए यह लाभप्रद है कि पंजाब के कुछ पानी को राजस्थान में पहुंचाया जाए। इस्का उपाय यह है कि हम बिजली की नेशनल ग्रिड की तर्ज पर एक पानी का नेशनल ग्रिड बनाएं। पंजाब अपने पानी को बेचे और राजस्थान उसे खरीदे। उससे फायदा यह होगा कि पंजाब और राजस्थान दोनों ही पानी की असल कीमत को समझेंगे। पंजाब अपने किसानों द्वारा पानी की बर्बादी को रोक कर, उस बचे हुए पानी को बेच कर समृद्ध होगा और राजस्थान खरीदे गये पानी का सदुपयोग करके समृद्ध होगा। लेकिन इस पानी को ले जाने के लिए किसी नदी को नाले की तरह उपयोग करना उचित नहीं है। सरकार नेशनल वाटर ग्रिड बनाये, पाइपों अथवा नहरों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य को पानी ले जाये।

आगामी समय में ग्लोबल वार्मिंग के चलते कम समय में तीव्र वर्षा होगी। पूर्व में यदि किसी स्थान पर साल में 90 दिन वर्षा होती थी तो भविष्य में वर्षा की मात्रा उतनी ही रहेगी लेकिन वह पानी 90 दिन के स्थान पर केवल 30 दिन में गिरेगा। ऐसे में बाढ़ का प्रकोप बढेगा जैसा कि हम इस समय देश के तमाम हिस्सों में देख रहे हैं। इस बढ़ते हुए संकट को हम नहरों के माध्यम से एक नदी के पानी को दूसरी नदी में ले जाकर नहीं संभाल पाएंगे, चूंकि तीव्र वर्षा के समय पानी की मात्रा अधिक होगी।

इसलिए सरकार को चाहिए कि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बजाय जहां पर पानी गिरता है वहीं पर उसे भूगर्भीय तालाबों में संगृहीत करने के उपाय करे। जिस प्रकार हम कुआं खोदकर नीचे से पानी निकालते हैं, उसी प्रकार रिचार्ज कुएं बनाये जा सकते हैं, जिनके माध्यम से हम बाढ़ के पानी को भूमि के अंदर विद्यमान तालाबों में प्रवेश करा सकते हैं। इस प्रकार के रिचार्ज कुओं को बनाना चाहिए और साथ-साथ तालाबों और चेक डैम को बनाकर जहां पर वर्षा का पानी गिर रहा है वहीं उसके संग्रहण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। पानी की खपत को भी कम करना होगा। अपने देश में पानी की 80 प्रतिशत खपत कृषि में होती है। इसका एक बड़ा हिस्सा गन्ना, मिन्था, लाल मिर्च और अंगूर जैसी विलासिता की फसलों के लिए होता है। इनका निर्यात भी भारी मात्रा में किया जाता है। हमें चाहिए कि कृषि में पानी की खपत कम करने के लिए इन फसलों का उत्पादन केवल उन क्षेत्रों में होने दें जहां बाढ़ आती है।

बाढ़ से जानमाल के होने वाले नुकसान को भी ध्यान में रखना होगा। बाढ़ को पूर्णतया रोकने के स्थान पर बाढ़ के साथ जीने की कला को विकसित करना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व गोरखपुर की बाढ़ का अध्ययन करने पर लोगों ने बताया कि गांवों को ऊंचे स्थानों पर बनाया जाता था। उन स्थानों पर हैन्डपम्प की व्यवस्था की जाती थी ताकि बाढ़ में पीने के पानी की परेशानी न हो। सड़कों के नीचे पानी के बहाव के पर्याप्त स्थान छोड़ दिए जाएं तो बाढ़ एक पतली चादर की तरह विस्तृत क्षेत्र में फैलकर बहती है और बाढ़ का पानी ऊंचा ज्यादा नहीं उठता है, चूंकि उस्के बहने की समुचित व्यवस्था बनी रहती है। अतएव बाढ़ के पानी से होने वाला नुकसान कम हो जाता है।

कहां जाये छोटा और नीरीह किसान?

महबूब आलम

छोटे और कमजोर किसान कर्ज लेकर या पैसे जुगाड़ कर खेती करते हैं और अपनी उपज के प्राप्त होते हीं उनकी पहली जरूरत नकद पैसों की होती है। उनकी इस जरूरत को जानने वाले बिचौलिये नकद में औने पौने दामों पर खरीद लेते हैं और अच्छी कीमत पर बेचते हैं। छोटे किसानों को कोल्ड स्टोरेज में अपनी उपज रखने की सुविधा भी नहीं होती। वहां सक्षम किसान पहले से ही जगह बुक करा लेते हैं। ऐसे में ऊंची कीमत पर कुछ खरीदने से ये ऐसा सोचना बेमानी होगा कि किसानों को अच्छी आमदनी भी हो रही है।

अक्सर ये खबर बनती है कि बाजार में सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, प्याज ने आंख से आंसू निकाल दिये, मिर्ची तीखी हुयी, आलू भी अब आम आदमी के पहुंच से हो रहा दूर, टमाटर अब सिर्फ देखने की चीज रह गयी है और हरी सब्जियां सिर्फ पैसे वाले ही खरीद रहे हैं।

02 मई 2018 की शाम अपनी बाइक खड़ी कर मैं सब्जी खरीदने के लिए बाज़ार में था। जैसे ही बाजार की ओर आगे बढ़ा मेरे कानों में लगातार 10 रुपया में 4 किलो.... 10 रुपया में 4 किलो.... 10 मे 4 .... 10 मे 4.....(टमाटर), 10 में डेढ़ किलो,.....(गाजर), 10 में 5 पीस..., 10 में.....5 (लौकी कम से कम 8 किलो), 10 रुपया में 2 किलो....., 10 में 2....., 10में 2.....(खीरा), 10 रुपये किलो....., 10 रुपये किलो.....(भिंडी) की आवाज़ आने लगी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले ये आवाज उस सब्जी बाजार में नहीं गुंजती थी लेकिन मेरा ध्यान शायद पहले उस ओर नहीं जाता था।

मैंने सोचा अचानक से बाज़ार को क्या हो गया है ? कोई सेल-वेल तो नहीं लगा है ! जहां हर तरह की सब्जी 10 रुपया मे एक से पाँच किलो तक....! सच कहता हूँ, सब्जियों के ये भाव सुन कर मैं खुश नहीं हुआ या मुझे बिलकुल अच्छा नहीं लगा। मेरी आँखों के सामने उन किसानों के चेहरे तैरने लगे जिनसे मैं कभी मिला करता था।

मैं यह सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, कि क्या ऐसी सेल का मजा कभी वे किसान भी ले पाते होंगे जिनके उपज के सेल से आज बाज़ार गुलज़ार है ? क्या कभी उन्हें भी बीज, खाद ऐसी सेल में खरीदने का मौका मिलता होगा ? इस महंगाई के दौर में..... जब चीज़ें रोज महंगी हो रही हैं, डीजल और पेट्रोल 70-75 रुपये लीटर बिक रहे हों तो ये सब्जियाँ आखिर इतनी सस्ती क्यूँ और कैसे हो रही है ? जाहिर है कुछ तो कारण होगा !

खैर..... मुझे सब्जी तो लेनी ही थी सो मैंने उसी भाव पर सब्जी की ख़रीदारी की। जब आलू लेने पहुंचा तो दुकान वाले ने बताया, सफ़ेद 16 रुपये और लाल 20 रुपये किलो। आलू भी खरीद ली। झोला लिए बाइक तक पहुंचा, बाइक में झोला टांगा, स्टार्ट किया और चल दिया। रास्ते भर और घर पहुँचने के बाद भी मेरे जेहन में कुछ सवाल कौंधते रहे -

वो ये कि जब बाज़ार में सब्जियों के ये भाव हैं तो बे-चारे (बे-चारा इसलिए की उनके पास कोई विकल्प नहीं होता) किसान ने आखिर किस भाव पर सब्जियाँ बेची होगी ?2022 तक कैसे उनकी आय दोगुनी (सरकारी दावों के अनुसार) हो जाएगी ?

कहीं इन व्यापारियों को सब्जियाँ मुफ्त में तो नहीं मिल गई होंगी ?

उन्होने (किसानों ने) सब्जियाँ फेक तो नहीं दी होगी, ?(जो अक्सर सुनने में आता है)

एक व्यापारी जब गाँव के किसान से सब्जी लेकर आता है तो उस पर उसे कई तरह के खर्च वहन करने होते हैं। मसलन उसके दिन भर की मजदूरी, भोजन-पानी, भाड़ा आदि इन सारे खर्चों को जोड़ दिया जाए तो यह खर्च कम से कम 15000 - 2000 रुपया तो ज़रूर होगा। अब यदि वह व्यापारी 1000 किलो भी सब्जी (जो संभव नहीं है) लाता है तो प्रतिकिलो उसे एक री डेढ रुपए का खर्च बैठता है। इसके बाद वह सब्जियों के भाव तय कर उसकी बिक्री करता है। अब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर उस व्यापारी कोकिस भाव मे ये सब्जियाँ मिली होंगी !

अब बात आलू की। संभवतः उस दिन, बाज़ार मे आलू सबसे महंगी बिक रही थी। कारण स्पष्ट है। वो किसानों के पास से निकल कर बाज़ार में नहीं आई थी। वो तो मोटे व्यापारियों के पास से निकली थी। इसलिए उसकी कीमत तय करने का अधिकार उन व्यापारियों के पास था न की इन खुदरा व्यापारियों के पास। इसलिए वो महंगी थीं औरसीजन आने तक आगे भी रहेंगी। जबकि यही आलू जब दिसंबर फरवरी तक किसानों के पास होती हैं तो किसानों को उसकी कीमत तय करने का अधिकार नहीं होता। कीमतव्यापारी तय करते हैं ।हमारे किसान के पास पूंजी की कमी है और अधिकांश किसान किसी से कर्ज़ लेकर खेती करते हैं। जब खेत से पैदावार निकलती है तो उन्हें उसे बेचने की जल्दी होती है और मोटे व्यापारी इसी का फायदा उठा कर औने-पौने दाम पर उनकी उपज खरीद लेते हैं और समय आने पर ऊंची कीमतों पर उसे बाज़ार में छोडते हैं। जो किसान (गिनती के) सक्षम हैं भी उन्हें कोल्ड स्टोरेज में आलू, गाजर, चुकंदर और अन्य सब्जियों को रखने की जगह नहीं मिलती क्यूंकी मोटे व्यापारी समय से पहले ही जगह की बुकिंग करा लेते हैं। ऐसे में किसानों की मजबूरी हो जाती है की वे व्यापारियों को अपनी उपज, उनके द्वारा तय कीमत पर बेच दें।

क्या ही अच्छा होता कि सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज वालों को जिन्हें कोल्ड स्टोर के निर्माण पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती। और कोई ऐसी व्यवस्था भी तय की जाती कि, छोटे और कमजोर किसान भी अपनी उपज को कोल्ड स्टोरेज में रख सकें। ताकि सचमुच किसान की आमदनी बढ सके।

औषधियों की रानी है तुलसी

तुलसी को 'हर्ब क्वीन' यानि कि 'औषधियों की रानी' कहा जाता है। भारत जैसे देश में तो तुलसी को साक्षात ईश्वर का दर्जा दिया गया है। हम अक्सर अपने बड़े-बुजुर्गों से तुलसी के पत्तों के गुणों के बारे में सुनते आए हैं। लेकिन हम इनके गुणों के बारे में जानते हुए भी इसका उपयोग कम ही करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तुलसी के पत्तों और फूलों में कई तरह के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो अनेक बीमारियों को रोकने व उसे जड़ से खत्म करने तक की ताकत रखते हैं। इसी वजह से कई बीमारियों की दवा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी शरीर के लिए अंदरूनी व बाहरी दोनों ही रूपों के लिए फायदेमंद है।

इसकी खास बात ये है कि यह व्यक्ति की तासीर के अनुसार काम करती है। तुलसी में अनेकानेक गुण होने के कारण तुलसी के पत्ते ही नहीं बल्कि इसकी टहनी, फूल, बीज आदि सभी भागों को आयुर्वेद और नैचुरोपैथी में भी इलाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैंसर जैसा रोग हो या सर्दी जुकाम, तुलसी का इस्तेमाल सदियों से होता चला आ रहा है।

रांची में सीएनजी कार

रांची : हाल ही में रांची में सीएनजी ऑटो के घोषणा के बाद अब मारूति कंपनी ने अपनी कई सीएनजी कारों को लांच करने की घोषणा की है। रांची में मारूति के डीलरों ने यह बात बतायी है कि कई पंसदीदा कारों के मॉडल अब सीएनजी वेरिएंट में भी मंगाया जा रहा है। यहां के खरीददारों ने भी पूछ ताछ कर इसकी जानकारी लेनी शुरू कर दी है। सीएनजी से कार चलाना पेट्रोल से सस्ता होता है।

आइसलैंड यूरोप का वह देश है जहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, आबादी बहुत ही विरल है, जहां प्रदूषण फैलाने वाला कुछ भी नहीं, वहां भी ग्लेशियर हो रहे हैं खत्म

जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ा ग्लेशियर ओकोजोकुल, आइसलैंड में शोक

- जलवायु परिवर्तन के कारण दर्जा खोनेवाला पहला ग्लेशियर बना आइसलैंड का ओकजोकुल
- आइसलैंड में ग्लेशियर का दर्जा खत्म होने पर शोक मनाया गया, पीएम ने जारी किया संदेश
- वैज्ञानिकों को आशंका है कि अगले 200 साल में सभी ग्लेशियर पूरी तरह से खत्म हो सकते हैं
- आइसलैंड में ग्लेशियर की याद में कांस्य पट्टिका का निर्माण किया गया है

आइसलैंड में पिछले रविवार को ग्लेशियर ओकजोकुल के लिए शोक मनाया गया। आधिकारिक तौर पर यह पहला ग्लेशियर है जिस्का दर्जा समाप्त कर दिया गया। आइसलैंड की प्रधानमंत्री ने शोक संदेश जारी करते हुए कहा कि इसे रोकने के लिए अब हमें भविष्य में क्या कदम उठाने हैं, यह सोचना होगा।

राजधानी रिक्जाविक आइसलैंड के निवासी अपने ग्लेशियर के खत्म हो जाने का शोक मना रहे हैं। रविवार को प्रधानमंत्री केटरिन जोकोबस्दोतियर के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह ने ग्लेशियर ओकजोकुल को श्रद्धांजलि दी। ओकजोकुल पहला ग्लेशियर है जिसका आधिकारिक तौर पर ग्लेशियर का दर्जा समाप्त कर दिया गया। अगले 200 साल में विश्व के सभी प्रमुख ग्लेशियर का हश्र ऐसा ही होने की आशंका जताई जा रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से जारी संदेश में कहा गया, 'यह हमारे लिए स्वीकार करने का वक्त है कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसे रोकने के लिए कौन से कदम उठाने हैं, इसकी भी हमें जानकारी है।'

ग्लेशियर का गायब होना बहुत ही चिंताजनक बात है इसे यह बात साबित होती है की आने वाले समय मे कई छोटे देश जो समुंद्र मे असन्ख्य टापुओ पर बसे हुए है खत्म हो जायेंगे फिर इन देशो की आबादी। ग्लेशियर के शोक में कांस्य पट्टिका का अनावरण किया गया जिसमें इसकी वर्तमान स्थिति बयान करने के साथ ही बाकी ग्लेशियर के भविष्य को लेकर आगाह किया गया है। आईसलैंड की प्रधानमंत्री कैटरीन

जैकोब्स्दोतिर, पर्यावरण मंत्री गुडमुंडुर इनगी गुडब्रॉन्डसन और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त मेरी रॉबिन्सन भी इस समारोह में शामिल हुए। राइस विश्वविद्यालय में एंथ्रोपॉलजी की एसोसिएट प्रोफेसर सायमीनी हावे ने जुलाई में ही इसकी स्थिति को लेकर आगाह किया था। उन्होंने कहा था, जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी पहचान खोने वाला यह पहला ग्लेशियर होगा।'

वैज्ञानिकों ने पहले ही जारी कर दी थी आशंका

ओकजोकुल आइसलैंड के पश्चिमी सब-आर्क-टिक हिस्से में ओक ज्वालामुखी पर स्थित था। पिछले कुछ वर्षों से लगातार यह ग्लेशियर पिघल रहा था और इसके खत्म होने की आशंका जताई जा रही थी। सैटलाइट इमेज में ग्लेशियर के 14 सितंबर 1986 की तस्वीरें जारी की गई थीं। बाईं ओर 1986 की तस्वीर है और दाईं तरफ 1 अगस्त 2019 की तस्वीर है। 1901 में ओकजुल 38 स्क्वॉयर फीट किलोमीटर में फैला था जो अब घटकर 1 स्क्वॉयर किलोमीटर से भी कम रह गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भविष्य में आनेवाले खतरों की शुरुआत है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने भविष्य में आइसलैंड के 400 ग्लेशियर के इसी तरह खत्म होने को लेकर चेतावनी जारी की है। हर साल आइसलैंड में करीब 11 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का अनुमान है कि अगर ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन इसी रफ्तार से होता रहा तो 2100 तक विश्व के आधे से अधिक ग्लेशियर पिघल जाएंगे।

गोंदा डैम में मछली पालन का ठेका किसी समिति को देने का विरोध, सैकड़ो परिवारों की रोजी रोटी छिन सकती है

रांची : कांके डैम संरक्षण समिति ने बीते सप्ताह नगर निगम,रांची के द्वारा कांके डैम में मछली पालन और बिक्री का ठेका किसी समिति को देने के निर्णरू का विरोध किया है। डैम से जुड़े हे सल, क रंजटोली, लक्ष्मी नगर, कठहलगोंदा, मिशन गली,मिशिर गोंदा,टिकली टोला,सोसो,नवासोसो,पतरागोंदा ,हथिया गोंदा समेत कई गाँवों के सैकड़ों स्थानीय लोगों को मछली पालन और बिक्री पर रोक लगाने के विरोध में 25 अगस्त को शाम चार बजे फुटबॉल मैदान,सोसो में ग्रामीणों और मत्स्यपालकों की सभा हुयी।

मालूम हो कि कांके डैम संरक्षण समिति ने कांके डैम के संरक्षण,संवर्धन और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार काम किया है। उसमें स्थानीय लोगों और मछुआरों का भी बड़ा योगदान रहा है। यह भी जानना आवश्यक है कि आज सौ से ज्यादा परिवार कांके डैम से मछली मार कर ही अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वैसे है जो यहाँ के रैयत हैं और किसी न किसी के बाप दादा का जमीन डैम निर्माण के समय जा चुका है। नगर निगम ने इन सैकड़ों लोगों के रोजगार को छीन लिया है और टेंडर के माध्यम से एक व्यावसायिक समूह को अपने व्यावसायिक हित के लिए काम करने की इजाजत दे दी।
संरक्षक अमृतेष पाठक ने कहा कि यह निर्णय गलत है और आगे इसके विरोध में आंदोलन भी किया जायेगा। हाल ही में कांके डैम संरक्षण समिति ने कांके डैम के किनारों पर सैकड़ो नीम के पौधे लगाये हैं और खुद उनकी सुरक्षा भी कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने दी अरूण जेटली को श्रद्धांजली

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में स्व अरूण जेटली जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा स्व जेटली जी के विचार सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अरुण जेटली जी के निधन के कारण मुख्यमंत्री रघुवर दास 25 अगस्त के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गये हैं। दुमका दौरा भी स्थगित कर दिया गया।

राज्यपाल ने शोक प्रकट किया

माननीया राज्यपाल ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली के निधन पर गहरा दुःख एवं शोक प्रकट किया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री जेटली एक कुशल राजनेता थे। वे विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण सक्रियता से कार्य करने हेतु तत्पर रहते थे। ईश्वर उनकी आत्मा को चिरशांति प्रदान करें एवं उनके परिजनों को इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

नींबू से सलाना कमाई 5 करोड़ रूपये

एक किसान अपने पौने दो एकड़ नीबू के बगीचे की लागत से परेशान था, सिर्फ इनकी लागत ही लाखों रुपए में पहुंच जाती थी। अभिषेक जैन ने इस बढ़ी लागत को कम करने के लिए बाजार से रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाएं लेनी बंद कर दी। पिछले तीन साल से जैविक तरीका अपनाने से इनकी हजारों रुपए की लागत कम हो गयी है। लागत कम होने से ये नीबू के बगीचे से बाजार भाव के हिसाब से सालाना पांच से छह लाख रुपए बचा लेते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर संग्रामपुर गाँव के अभिषेक जैन (34 वर्ष) बीकॉम करने के बाद मार्बल के बिजनेस से जुड़ गये। अभिषेक जैन गाँव कनेक्शन को फोन पर बताते हैं, "पिता के देहांत के बाद बिजनेस छोड़कर पुश्तैनी जमीन को सम्भालना पड़ा। खेती करने के दो तीन साल बाद मैंने ये अनुभव किया कि एक तिहाई खर्चा सिर्फ खाद और दवाइयों में निकल जाता है। इस बढ़ती लागत को कम करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया था।" वो आगे बताते हैं, "लागत कम करने के लिए तीन साल पहले साकेत ग्रुप के बारे में पता चला, जो जैविक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण देता है। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद अब हम पूरी तरह से नीबू के बगीचे को जैविक ढंग से कर रहे हैं, इससे जो लागत पहले 33 प्रतिशत आती थी अब वो 10 प्रतिशत पर आ गयी है।

पूर्व प्रधानमंत्री बाजपेयी ने भी बाढ और सूखे से निबटने के लिये नदियों को जोडने़ की बात कही थी, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा?

नदियों को आपस में जोड़ना एक आत्मघाती कदम होगा

मिहिर शाह

अगर नदियों को जोडने़ की परियोजना अमल में लाई जाती है तो भारत में मौसम चक्र के सबसे अहम किरदार मॉनसून पर भी गहरा असर पड़ सकता है। बता रहे हैं *मिहिर शाह*

देश भर में जल संकट गहराने के साथ ही विज्ञान एवं अध्यात्म दोनों के बुनियादी सिद्धातों के उल्लंघन के लिए तैयार होने की सीमा और हमारा दुःसाहस भी बढ़ चुका है। अपनी गलतियों से सबक सीखने के बजाय हम गलत रास्ते पर ही आगे बढने़ से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। भारत की नदियों को एक-दूसरे से जोडने़ का प्रस्ताव दोषपूर्ण धारणाओं की एक पूरी शृंखला पर आधारित है। कहा जाता है कि एक ही समय पर भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ और कुछ हिस्सों में सूखा होता है, लिहाजा पानी की अधिकता वाले क्षेत्रों से किल्लत वाले क्षेत्रों में पानी पहुंचा दिया जाए तो सबकी समस्या दूर हो जाएगी। सवाल है कि क्या वाकई में भारत के कुछ इलाकों में बहुत अधिक पानी है? पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में सोचिए। क्या आपको पता था कि धरती पर सर्वाधिक बारिश वाली जगहों में शुमार सोहरा (पहले चेरापूंजी के नाम से मशहूर) अब पीने लायक पानी की कमी से गुजर रहा है? जल प्रबंधन की पुरानी परिपाटी को इसकी वजह माना जा सकता है जिसमें अपने जलग्रहण क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन कर पाने में हम नाकाम रहे हैं। इसके अलावा प्राकृतिक झरनों को हमने बरबाद कर दिया और भूमिगत जल का खूब दोहन किया। जलवायु परिवर्तन ने हालात को और भी खराब कर दिया है। आज मेरा संगठन 'समाज प्रगति सहयोग' इस जटिल समस्या का समाधान तलाशने में लगा हुआ है लेकिन मैं बता सकता हूं कि सोहरा में महज 70,000 लोग होने और दिल्ली की तुलना में वहां दस गुना बारिश होने के बावजूद किसी और के लिए वहां अतिरिक्त जल नहीं रह गया है। भारतीय उप-महाद्वीप में मॉनसून पर निर्भरता के चलते नदियों में अधिक पानी होने की स्थिति लगभग एक समय पर ही पैदा होती है। एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि भारत के जल-अधिकता वाले नदी घाटी क्षेत्रों में मॉनसूनी बारिश में खासी कमी आई है। इस तरह नदी-जोड़ परियोजना की मूल धारणा ही सवालों के घेरे में आ जाती है।

यह बड़ी राहत की बात है कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में नदी-जोड़ परियोजना का जिक्र तक नहीं किया है। शायद यह नए जलशक्ति मंत्री की सोच की स्पष्टता का संकेत देता है। लेकिन इस विचार के समय-समय पर सामने आने की बात को ध्यान में रखें तो इस खतरनाक विचार का ध्यानपूर्वक अवलोकन जरूरी है। नदी-जोड़ परियोजना के तहत हिमालयी खंड में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर बड़े बांधों और उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों के जल-अधिकता वाले इलाकों में पानी जमा करने की योजना है। फिर इस पानी को नहरों के जरिये पानी की कमी वाले मध्य, दक्षिणी एवं पश्चिमी इलाकों में भेजा जाएगा। वहीं परियोजना के प्रायद्वीपीय खंड के मुताबिक प्रायद्वीप में मौजूद नदियों के अतिरिक्त पानी को भी जमा कर दक्षिणी एवं पश्चिमी हिस्सों में भेजा जाएगा। इस परियोजना के तहत कुल 44 नदियों को 9,600 किलोमीटर लंबी नहरों के जरिये जोडने़ की तैयारी है जिस पर 11 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। यह परियोजना की असली लागत का एक अनुमान भर है और असली लागत इससे काफी अधिक रह सकती है। क्रियान्वयन में विलंब की आशंकाओं और ऊर्जा मद के अलावा खेती एवं जंगल को होने वाले नुकसान और मानवीय विस्थापन पर होने वाला खर्च भी इसमें शामिल नहीं है। असली विडंबना यह है कि भारत की स्थलीय संरचना देखते हुए नदियों को जोडने़ की जो परिकल्पना की गई है, वह मध्य एवं पश्चिमी भारत के असली सूखाग्रस्त इलाकों को दरकिनार कर देती है। ये इलाके समुद्र तल से 300-1,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं।

हाल में वैज्ञानिकों ने भारतीय नदी प्रणाली में इतने बड़े स्तर पर होने वाले दखल के संभावित असर का बारीकी से परीक्षण शुरू कर दिया है। परियोजना में शामिल 44 में से 29 नदियों के बारे में 2018 में किए गए एक अध्ययन के मुताबिक इस परियोजना की वजह से 3,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डूब जाएगा और करीब सात लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। नहरें बनते समय विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या अलग होगी। यह 29 में से 24 नदियों के प्रवाह को भी बाधित करेगा जिससे गीली जमीन (वेटलैंड) एवं नदियों के चौड़े मुहाने (एस्चुअरी) तक पहुंचने वाला पानी भी कम हो जाएगा। जलमार्ग में नए दूषणकारी तत्त्व, प्रजातियां और बीमारियां पैदा करने वाले एजेंट मिलेंगे। भारतीय उप-महाद्वीप के पहले से ही संकटग्रस्त डेल्टा क्षेत्र नदियों से लाई जाने वाली गाद में 87 फीसदी तक कमी हो जाने से और भी अधिक खतरे में पड़ जाएंगे। पानी के प्रवाह में कमी आने का असर डेल्टा क्षेत्रों में खारेपन पर असर पड़ेगा जिससे आगे चलकर समुद्र का जलस्तर बढने़ और भूमिगत जल एवं नदी जल के खारे होने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। नदियों एवं डेल्टा क्षेत्रों में खारापन बढने़ से नदियों के मुहाने पर गिरने वाली गाद में और कमी आएगी। दुर्लभ पारिस्थितिकी एवं अहम कृषि क्षेत्र तूफानों की संख्या बढने़, नदियों की बाढ़ और खारापन बढने़ को लेकर अधिक संवेदनशील हो जाएंगे।

कृष्णा, गोदावरी एवं महानदी नदियों में प्राकृतिक एवं मानव-निर्मित कारणों से पानी का प्रवाह पहले से ही धीमा हो चुका है। ऐसे में नदी-जोड़ परियोजना केवल इस समस्या को बढ़ाने का ही काम करेगी। यह कोलोरेडो, नील, सिंधु एवं येलो नदी प्रणालियों से मिलती-जुलती स्थिति है जहां ऐसी ही परियोजना सीमित स्तर पर लागू करने की कोशिश की गई थी। एलिमेंटा अध्ययन का दावा है कि 'भारत की नदी-जोड़ परियोजना अमेरिका में एक नदी प्रणाली से दूसरी प्रणाली तक पानी पहुंचाने की सबसे बड़ी परियोजना से भी 50-100 गुनी बड़ी है और इसके मानव इतिहास की सबसे बड़ी निर्माण परियोजना बनने की संभावना है।'

आखिर में, हमें यह मान लेना चाहिए कि नदी-जोड़ परियोजना भारत की मॉनसून प्रणाली की समग्रता को ही गहराई से प्रभावित कर सकती है। नदियों के मीठे जल के लगातार समुद्र में जाने से ही बंगाल की खाड़ी के ऊपरी स्तरों में पानी में लवणता का निम्न स्तर और निम्न सघनता बनी रहती है। यह समुद्र में पानी के स्तर का ऊंचा तापमान (28 डिग्री सेल्सियस से अधिक) बने रहने की वजह है जिससे समुद्री इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है और मॉनसूनी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है। उप-महाद्वीप के अधिकांश हिस्से में बारिश काफी हद तक कम खारे पानी के इस जलस्तर से ही निर्धारित होती है। लेकिन नदी-जोड़ परियोजना के तहत नदियों के मार्ग में बड़े अवरोध खड़े करने से समुद्र तक पहुंचने वाले मीठे पानी का प्रवाह बाधित होगा जिसका उप-महाद्वीप में जलवायु एवं बारिश पर गंभीर दीर्घकालिक दुष्परिणाम हो सकते हैं जो आबादी के बड़े हिस्से की आजीविका को भी खतरे में डाल सकता है।

सच तो यह है कि सड़कों एवं बिजली आपूर्ति की तरह नदियों को इंसानों ने नहीं बनाया है जिनका मनमाने ढंग से बेजा इस्तेमाल किया जा सके। नदियां एक जीती-जागती पारिस्थितिकी हैं जिनका जन्म हजारों वर्षों के भीतर क्रमिक रूप से होता रहा है। लेकिन हम अपने अहंकार के वशीभूत होकर नदियों को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी नदी जल प्रणालियों में नई जान फूंकने, प्रकृति के नाजुक धागे को उलझाने के बजाय विनम्रता एवं समझदारी दिखाते हुए विज्ञान एवं अध्यात्म का समावेश करने की दिशा में आगे बढ़ें।

लेखक समाज प्रगति सहयोग के सह-संस्थापक हैं

किसानों से दिन दहाड़े डकैती करते नकली खाद और बीज विक्रेता, बेचते है एक्सपायरी कीटनाशक, खाद

कमलेश कुमार सिंह

पटना: आज किसानों को कैसे लूटा जा रहा है। इस पर शायद ही कभी अखबारों या टीवी न्यूज़ चैनलों पर खबरें प्रकाशित या प्रदर्शित होतीं हैं । आखिर कभी आपने सोचा है कि किसानों को मनोवांछित फसल का उत्पादन क्यों नहीं हो पाता। हां, कहा जाता है कि मौसम की मार किसानों पर, बाढ़ आया सूखा आया। फसल तबाह हो गए, बर्बाद हो गए।

हां, इसमें सच्चाई है। इससे भला कोई इंकार कैसे कर सकता है, लेकिन मौजूदा दौर में फसलों के कम उत्पादन के पीछे जमीन की उर्वरा शक्ति की कमी के अलावा एक बहुत बड़ी समस्या है । दिनदहाड़े उनके डकैती हो रही है। कैसे? सभी खाद बीज विक्रेताओं पर तो यह बात लागू नहीं होती, लेकिन हां लगभग 50 फ़ीसदी से ज्यादा खाद बीज विक्रेता किसानों को दिनदहाड़े लूट रहे हैं। उनकी मेहनत की कमाई से अपनी जेबें भर रहे हैं। दरअसल बीज विक्रेता बड़े पैमाने पर गोरख धंधा कर रहे हैं। एक्सपायर खाद, बीज व कीटनाशकों को बेचकर। अब भला आप सोचेंगे कि हां अधिकतर किसान तो अनपढ़ हैं वह इनके पैकेट पर दर्ज या चस्पा या छपे उत्पादन की तारीख व एक्सपायरी तारीख को पढ़ नहीं पाते होंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्पादन की तारीख भी दुरुस्त है। और एक्सपायरी डेट भी दुरुस्त है। ऐसे में आपके जेहन में एक सवाल जन्म लेगा, तो इसमें गोरख धंधा है, क्या?

जनाब बहुत बड़ा गोरखधंधा खाद बीज कीटनाशक आदि खेती किसानी के डिब्बाबंद उत्पादों में। जब ये एक्सपायर हो जाते हैं, तब ऐसे विक्रेता इन्हें कचड़े मैं नहीं फेंकते या कंपनी को नहीं लौटाते। बल्कि कुछ स्थानीय प्रिंटरों की मदद से एक गंदा खेल खेलते हैं। सबसे पहले उस डब्बे पर दर्ज तारीखों को बड़ी सफाई से मिटाया जाता है। मानो पहले से कोई अंक दर्ज ही ना हो। बिल्कुल कोरा।उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की मदद से हुबहू कंपनी की तरह फिर से उस पर नई तारीखों के साथ प्रिंट कर दिया जाता है। अब किसान के सामने जब ऐसे उत्पाद आते हैं तो वह वही देखते पढ़ते हैं जो उन्हें दिखाया पढ़ाया जाता है। किसान खुशी खुशी ऐसे उत्पाद लेकर अपने खेतों में जाते हैं बीज बोते हैं उसे अच्छी तरह फलने फूलने के लिए खाद डालते हैं और कीटों के आक्रमण से बचाने के लिए ऐसे ही कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। अब भला ऐसे में कैसे फसल अच्छा होगा? कीटों से कैसे बचाव होगा। स्थानीय प्रिंटरों को एक रुपैया या 2 प्रति पैकेट पर छपाई का पैसा मिल जाता है। एक ऐसे ही प्रिंटर से जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने बड़ी चतुराई से जवाब देते हुए कहा ऐसा मैं नहीं करूंगा तो कोई दूसरा कर लेगा, तब तो मेरी कमाई जाति रहेगी। हां, मैं जानता हूं कि ऐसा करना गलत है, लेकिन पापी पेट का सवाल है।

कुछ किसानों से जब इस मुद्दे पर बात की गई तो उनका सबसे पहले ऐसे किसी भी ठगी, डकैती, लूट हो भी सकता है की बात से ही भौचक्के रह गए। कुछ ने कहा, हम तो सालों से उस फलाने बीज विक्रेता की दुकान से ही सब कुछ खरीदते हैं। हां कई बार फसल तो काफी अच्छी होती है और कई बार खराब। हमें तो लगता है यह मौसम की मार है या मिट्टी मैं पहले सी क्षमता नहीं रही। लेकिन बाबू हम तो पैकेट पर तारीख ही देकर खरीदेंगे ना अब ऐसा झोल मोल होगा तो हम कैसे पता करेंगे। अब बात सरकार की इंसान के लिए बिकने वाली दवाइयों एवं अन्य खाद्य सामग्रियों की जांच के लिए फूड इंस्पेक्टर या ड्रग इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं। अधिकतर लोगों को पता है यह इंस्पेक्टर लोग कैसे काम करते हैं। अपनी जेबे भरने के अलावा शायद ही कुछ करते हैं। सभी नहीं अधिकतर के बारे में ऐसा ही मत है।

क्या किसानों के लिए बेची जा रही खाद बीज कीटनाशक की जांच के लिए कोई तैनात है? क्या अगर है तो इतने बड़े पैमाने पर दिनदहाड़े ऐसी डकैती हो कैसे हो रही है? किसान रो रहे हैं। कुछ कीजिए उनके आंसू को पूछिए। ऐसे काला कारोबार करने वालों पर सख्ती कीजिए। हमारे अन्नदाता को बचाइए। जागिये सरकार जागिये।

माननीया राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनजातीय अखरा 2019 का शुभारंभ किया

आसाम के धृतिमान बोरा ने बांस का बोतल ही बना डाला। प्लास्टिक के हानिकारक प्रभाव को इस बोतल के उपयोग करने से कम किया जा सकता है।

फोटो न्यूज

प्लासिटक के थैले का त्याग किजिये और ये खास थैला उपयोग करें। इसमें बने अलग अलग पॉकेट सामान रखने में भी आसान हैं।

करमटोली तालाब की ये तस्वीर कुछ महिनो पहले की है । इसके सौंदर्यीकरण में इतना ज्यादा कंक्रीट उपयोग हुआ है कि अब ये तालाब पहले की तरह रिचार्ज नहीं हो पायेगा

आपका गांव कितना स्मार्ट.

शहरों की ओर लगातार हो रहे पलायन को रोकने के लिए गांवों के हालात बेहतर बनाने होंगे। देश में करीब ढाई लाख पंचायतें हैं। अगर एक पंचायत के विकास की जिम्मेदारी सीएसआर वाली एक कंपनी को दे दी जाए तो गांवों में बदलाव दिखने लगेगा

उमेश चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार

मानसून के असमान वितरण के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाली की कहानियां एक बार फिर सामने हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कई गांव पानी में डूबे हैं। जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और असम समेत पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्से बारिश की तबाही के आदी रहे हैं। शरद ऋतु की ठंडक जैसे-जैसे नजदीक आती है, पता चलता है कि मानसूनी बौछार ने प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार पानी देने के साथ-साथ कितनी सारी चीजें छीन भी ली हैं। बिजली के टूटे खंभे, टूटी सड़कें, आवागमन के ध्वस्त साधन और बड़ी बिल्डिंगों में आईं दरारें- हर साल हमें ये बारिश के साइड इफेक्ट्स की तरह नजर आते हैं।

उपेक्षित पड़े गांव

ज्यादा बारिश वाले इलाके के शहरों में तो फिर भी बुनियादी ढांचा जल्दी दोबारा खड़ा कर लिया जाता है, लेकिन देहाती इलाकों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसका असर देहात के रोजी-रोजगार पर पड़ता है और फिर शहरोन्मुखी पलायन बढ़ने लगता है। प्रसिद्ध ललित निबंधकार और गंवई गंध के चितेरे विवेकी राय ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, 'गांव अब पगडंडियों से निकलकर सड़क पर आ गया है लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी आत्मा मरी है। विकास के मौजूदा मॉडल के बावजूद उसके यहां शहरों की तुलना में बुनियादी सुविधाएं कम हुई हैं। आज गांव की इच्छा शहर बनने की है लेकिन नौकरशाही के रवैये के चलते गांव न तो शहर बन पा रहा है और न ही गांव रह गया है।'

हाथ से बने पारंपरिक खिलौनों को लील गया स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक गजट

अब इनकी कोई पूछ नहीं

चुनिया-मुनिया, मुन्ना भइया। लेकिन बदलते हुए दौर में तकनीक ने बच्चों के खेल का पूरा परिदृश्य बदल लिया है। अब वह टीवी से चिपका रहता है। उसे डोरेमौन पसंद है, सीनचैन देखता है..उसी की तरह ऐक्टिंग करता है। हमेंशा इलेक्ट्रानिक गजट से चिपका रहता है। उसी का परिणाम है कि रोज बाजार में नए-नए आकर्षक उत्पाद अपनी धाक जमा रहे हैं, हाट-बाजार में इलैक्ट्रॉनिक खिलौने अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बदले हुए परिवेश में हाथ से की गई कारीगरी और उसके द्वारा तैयार किये गये उत्पादों का बाजार सिमटता जा रहा है। वो कारीगर जो कभी बच्चों के लिए बड़े शौक से खिलौने बनाया करता था, वो आज भी इन खिलौनों को बना रहा है लेकिन सिर्फ सजावट के लिए। आज ना तो कोई इन खिलौनों से खेलना चाहता है और ना ही इन्हे पसंद करता है। हां घर में सजावट के लिए इन्हे पसंद किया जा सकता है लेकिन अगर बच्चों को ये खिलौने खेलने के लिए दे दिए जाएं तो वो इन्हे पसंद नहीं करेंगे। रांची में पहले कभी कभार ताड़ के पत्तों जैसी किसी घास से बुन कर सुंदर फूल एवं कई कलाकृतियों के गढने वाले कलाकार दिखाई देते थे, अब वो शायद ही कभी दिखते हैं। ठिक ऐसे ही मेलों से पारंपरिक खिलौनों को बेचने वाले भी कम होते जा रहे हैं। आज के बच्चे उसे खरीदने के लिये रोते नहीं और न ही जिद करते हैं।

ऐसा हो सकता है भविष्य

कभी दूसरों पर आश्रित रहने वाले झारखंड ने मत्स्य पालन के लिये अपने प्राकृतिक संसाधनों को पहचाना और योजना बना कर उसका उचित दोहन किया

नीली क्रांतिःझारखंड कैसे बना मछली उत्पादन में चैंपियन

रांची : झारखंड सरकार की उपलब्धियों में से एक है राज्य का मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना। आज झारखंड में दूसरे राज्यों से भी मछुआरे मछली उत्पादन की तकनीक देखने सीखने आते हैं। इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ मछली उत्पादन करना ही नहीं है, बल्कि राज्य के मछुआरों को यह विश्वास दिलाना कि इस काम में सरकार साथ है, वह सुरक्षित हैं और उन्हे आर्थिक मदद के अलावा हर तरह की सुरक्षा दी जायेगी। कभी मछली के लिये झारखंड बाहर के राज्यों पर निर्भर था लेकिन एक बार विश्वास के कायम होते ही राज्य के मछुआरे सरकार के प्रयासों से जुड़ते चले गये और मत्स्य विभाग के योजनाओं ने झारखंड को मछली उत्पादन में अग्रणी बना दिया। इसे ***नीली क्रांति*** का नाम दिया गया।

झारखंड में तालाबों और बड़े डैमों की बहुतायत है। सबसे पहले इन तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार की योजना पर अमल हुआ। इस योजना के तहत विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों में 25 करोड़ उन्नत मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया। तथा इसकी बिक्री मत्स्य कृषकों को की जाती है।निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु , राज्य के मत्स्य कृषकों के पास उपलब्ध जलसंसाधन के समुचित लाभ उपयोग के लिये जाने के लिये कुल 7500 मत्स्य बीज उत्पादकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को उनके जल क्षेत्र के अनुरूप अनुदान पर अधिकतम 20 लाख स्पॉन दिये जाने की भी योजना है। कुल मिला कर राज्य में 1500 करोड़ मत्स्य स्पॉन संचित कर निजी मत्स्य बीज उत्पादकों द्वारा मत्स्य बीज तैयार किये जायेंगे। इस कार्यक्रम के लिये मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन के क्रय पर फीड एवं फ्राइ कैचिंग नेट उपलब्ध कराया जायेगा। जलाशय के समीप रहने वाले समिति, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले गरीब मछुआरों को जलाशय में मछली की उपलब्धता मिले इसके लिये साढे तीन सौ करोड़ स्पॉन का जलशयों में इन सीटू संचयन तथा चार सौ पंद्रह लाख मेजर कार्प एवं 55 लाख ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन कराया गया।

मत्स्य प्रसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत राज्य में मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों एवं इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचीकरण एवं बैंक खाते के आधार सीडिंग के लिये कृषकों का सर्वे किया जाता है साथ ही उत्पादकों से सीधे संवाद स्थापित करने के लिये उन्हें मोबाइल रिचार्ज कूपन भी उपलब्ध कराया जाता है। मछलीपालन के क्षेत्र में तीन दिवसीय, पांच दिवसीय एवं कार्यशाला का आयोजन राज्य स्तरीय मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र रांची करता है। इन प्रशिक्षण कार्यों का मुख्य उद्देश्य मत्स्य कृषकों के सम्मुख मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य पालन में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण एवं प्रायोगिकि प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना है। विभाग के वरीय पदाधिकारियों , राज्य एवं राज्य के बाहर के आगंतुक वरीय

पदाधिकारियों एवं वैज्ञानिकों द्वारा भी कभी कभी विशेष कक्षायें ली जाती हैं। इस वर्ष कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रगतिशील मत्स्य कृषकों के लिये दो चरणों में 14 एवं 7 दिन के रूप में कुल 21 दिन के रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण का भी आयोजन हुआ । संपूर्ण राज्य में प्रखंड - पंचायत पर गोष्ठि का भी आयोजन किया जाता है। जिसमें मुख्यतः स्थानीय परिवेश में पनदाधिकारियों कर्मचारियों द्वारा मत्स्य कृषकों के बीच विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुये उनके साथ मछली पनालन से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर विस्तार पूर्व चर्चा की जाती है। अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत पायलय्ट प्रोजेक्ट के रूप में विभागीय प्रक्षेत्र में पर्ल कल्चर का कार्य भी प्रारंभ किया जाना है। **झास्कोफिश को अनुदान योजना :** मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का राज्य स्तरीय सहकारी महासंघ के रूप में झास्कोफिश का गठन किया गया है। झास्कोफिश द्वारा झारखंड में कार्यरत मत्स्यजीवरी सहयोग समितियों के प्रबंधन के मछुआ सदस्यों को मत्स्य शिकारमाही का उचित मूल्य उपलब्ध कराने मछलियों के विपणन में सहायता और मछुआरों के लिये कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने की योजना है। इस योजना से राज्य में सहकारिता के आधार पर मत्स्यजीवी सहयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धी और मत्स्य पालको के आय आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये उन्हें मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जायेगी।

मत्स्य विपणन योजना : इस योजना का ध्येय राज्य की जनता को हाइजेनिक कंडीशन में मछलियां उपलब्ध कराये जाने के लिये विपणन विक्रेताओं को चिन्हित कर मछलियों के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिये स्टॉल उपकरण ऑटोरिक्शा फिश रिटैलिंग कियोस्क अनुदान पर उपकरण के साथ साथ सीआइएफटी द्वारा तकनीकी सहायता दी जाती है।

मत्स्य रियरिंग तालाबों का निर्माणः इस योजना में राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढाने के लिये तालाब निर्माण कराये जा रहे हैं।

फीड बेस्ड फिशरीज : राज्य में मछली केउत्पादन को बढाने के लिये यह योजना है। इसमें मत्स्य कृषकों को प्रति किलोग्राम फीड खरीदने पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

वेद व्यास आवास योजना : गरीब मछुआरों को मोबाइल देन के साथ ही सवा लाख रूपये दिये जाते हैं। मकान का निर्माण लाभूक स्यवं करवाता है।

छोटे हैचरी का निर्माण करवाया जा रहा है जिसे युवा समूह संचालित करेंगे। साथ ही मछुआरों के बीमा की योजना भी लागू की गयी है। जिसमें आकस्मिक निधन पर दो लाख और अपंगता की स्थिति में 1 लाख रूपये बीमा भुगतान किया जाता है। आगे आइओटी योजना लागू होना है जिसमें पानी की गुणवत्ता भी जांची जायेगी। साथ में वहां ऑक्सीजन की घुलनशीलता भी देखी जायेगी। ताकी उस तालाब का उपचार कर मत्स्य पालन योग्य बनाया जा सके।

E ZONE CARE

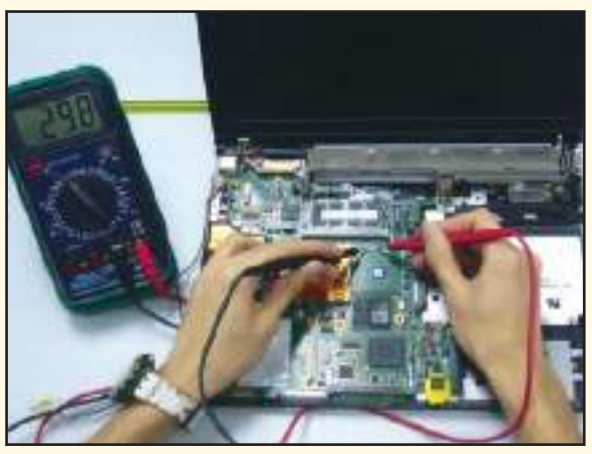

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty
info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511 Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

सन कम्युनिकेशन द्वारा अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2 टीवीएस गली रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित एवं मैसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित। प्रकाशक सह कार्यकारी संपादक : मनोरंजन सिंह, प्रधान संपादक : अभिषेक सिंह, संपादकः मनोज कुमार शर्मा, प्रबंध संपादक : डॉ. मंगला प्रसाद मिश्र, उपसंपादक : महबूब आलम, संपादकीय सलाहकारःमुकेश रंजन सिंह, प्रसार प्रबंधक : इंतेखाब अहमद। आर.एन.आइ. नंबर : JHAHIN00962. email:greenrevolt2019@gmail.com. Ph. 8539978825,8825374626. इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन ही होंगे।